NCPEDP - Javed Abidi Fellowship on Disability

Supported by Azim Premji Foundation

Baseline Report

जाविद खां

jkman654@gmail.com

सोहरापुर (महेवा, जालौन) उत्तर प्रदेश

Inclusion of Disabled Persons in livelihood schemes of Government

(सरकार की आजीविका योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों का समावेशन)

कार्यकारी सारांश

यह स्टडी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की तीन (चुर्खी मुसमरिया और खैरई) ग्राम पंचायतो में ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग युवाओ के लिय रोजगार के साधन जुटाने के लिए उनकी आधारभूत स्थिति का आकलन करने हेतु यह सर्वेक्षण किया गया इस सर्वेक्षण के माध्यम से दिव्यांगजनों को उनकी आजीविका जुटाने के लिए सरकार व संस्थाओं के द्वारा उनकी जरूरतों व समस्याओं को सामने लाकर उनको समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के प्रयास से की गई है |

ग्रामीण स्तर पर दिव्यांगजन को आजीविका जुटाने के लिए अनेकों माध्यम है | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना परंतु जमीनी स्तर पर विकलांग युवाओ में जागरूकता की कमी है शिक्षा का स्तर कमजोर है , कौशल की कमी है| सर्वेक्षण के अनुसार दिव्यांग युवाओ की समस्याओं का चिन्हाकंन के अनुरूप समस्याओं का समाधान पंचायत व समुदाय के साथ मिलकर लगातार कम्युनिकेशन मिटिंग में दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी दी जाए साथ ही दिव्यांगजनों को रोजगार व स्वरोजगार के प्रीति प्रोत्साहित किया जाए |

यहां पर आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन है यहां पर मिश्रित जलवायु पाई जाती है जिससे रवि, खरीफ और जायद् की फसलें होती हैं यहां पर मटर की खेती बहुत ही अच्छी होती है और मटर का निर्यात विदेशो में किया जाता है|

राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो 36% दिव्यांगजनों के पास रोजगार है और वही 64% लोगों के पास रोजगार नहीं है| इसमें पुरुष कामगारों की संख्या 47% है और महिला कामगारों की संख्या 23% है ग्रामीण भारत में, 25% महिला दिव्यांग काम कर रही हैं, जबकि शहरी भारत में,संगत आंकड़ा 16% है।[1]

सर्वे में जिन लोगों से मदद ली गई है वह (सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार, सरकारी अधिकारी,ग्राम पंचायत सदस्य, दिव्यांगजन, व मेंटर) सामाजिक रुप से सक्रिय सदस्य थे|

[1] Persons with Disabilities (Divyangjan) in India - A Statistical Profile : 2021- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nhfdc.nic.in/upload/nhfdc/Persons_Disabilities_31mar21.pdf

Contents

कार्यकारी सारांश..... 2

1 अनुभाग 1..... 4

2 अनुभाग 2..... 6

3 अनुभाग 3.....10

4 अनुभाग 4.....29

5 अनुभाग 5.....31

1 अनुभाग 1

पृष्ठभूमि:

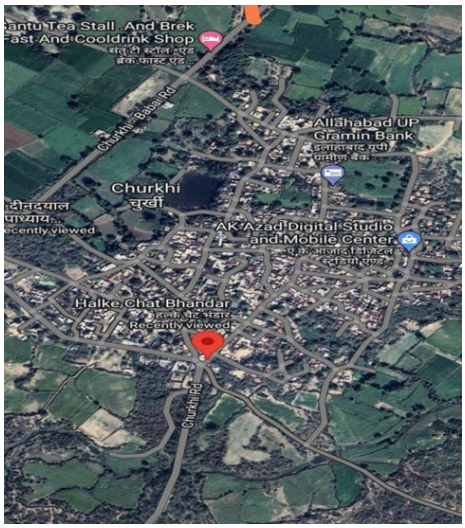

Maheva (village)
Latitude 26.077388 Longitude

ग्राम पंचायत चुर्खी, मुसमरिया और खैरई तहसील कालपी, जिला जालौन और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड से जुड़ा होने के कारण इन गाँवो का अपना प्राचीन इतिहास है| इस गांव के लोग बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करते हैं ।

ग्राम चुर्खी का इतिहासिक[2] अहमियत यह है की,यह झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सशक्त महिला राजा के रूप में थी, उनकी मौसेरी बहन गोपीकाबाई, चुर्खी ग्राम की रहने वाली थी | यहां मराठा साम्राज्य का शासन, अंग्रेजों के शासन काल में चलता था | 1857 की क्रांति के बाद पूरे देश में विद्रोह की एक लहर दौड़ गई; इसी विद्रोह के दौरान महारानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया और युद्ध के दौरान महारानी लक्ष्मी बाई 22 मई सन 1858 में वह 600 सैनिकों को परास्त करने के बाद, वह है अटरिया मुसमरिया ग्राम होते हुए ग्राम चुर्खी में अपनी बहन के घर 22 मई 1858 में उन्होंने रात्रि विश्राम किया, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं | सन 1932 में अंग्रेजों के शासन के समय से चुर्खी में पुलिस थाना स्थापित है। तहसील का नाम कालपी है जो की दूरी गांव से 26 किलो मीटर है। [3]जिला मुख्यालय का नाम जालौन है,गांव से इसकी दूरी 20 किलो मीटर है। सेंसस 2011 के अनुसार की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गाँव की कुल आबादी 4152 है, जिसमें पुरुष संख्या 2279 और महिला संख्या 1873 है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गांव की कुल 4152 आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर 822 महिलाएं हैं।गांव की साक्षरता दर 51.4 % है | महिलाओं की साक्षरता दर 17.8% है | गांव में 6 साल से कम उम्र के प्रति 1000 लड़कों पर 924 लड़कियां हैं। चुर्खी गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 824.51 हेक्टेयर है। चुर्खी का जनसंख्या घनत्व 5 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। गांव में कुल घरों की संख्या 709 है । [4]गाँव में काम करने वाले लोग 51.4% है | नदई (3 किमी), बम्हौरा (4 किमी), सरसई (4 किमी), बम्हौरी खुर्द (5 किमी), मुसमिरया (5 किमी) चुर्खी के नजदीकी गांव हैं। चुर्खी पश्चिम की ओर जालौन ब्लॉक, उत्तर की ओर कुठौंद ब्लॉक, दक्षिण की ओर डकोर ब्लॉक से घिरा हुआ है। कृषि इस गांव का मुख्य पेशा है |

[2] Jagran https://www.jagran.com/lite/uttar-pradesh/jhansi-city-22795112.html
[3] http://www.onefivenine.com/village.dont?method=displayVillage&villageId=193087
[4] https://www.onefivenine.com/india/census/village/Jalaun-/Kalpi-/Churkhi

जलवायु मिटटी व् उसके प्रकार

चुर्खी[5] में एक मिश्रित जलवायु है, जिसमें गर्मियों में तापमान अधिक और सर्दियों में कम होता है। [6]सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 40-50% रहती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान वर्षा को छोड़कर, उरई जिले की जलवायु गर्म गर्मी और सामान्य सूखापन की विशेषता है। वर्ष में चार ऋतुएँ होती हैं। ठंड का मौसम दिसंबर से फरवरी तक रहता है; जनवरी का न्यूनतम तापमान 7.1 सी है। गर्म मौसम मार्च से जून के पहले सप्ताह तक है। मई 42.1 C के औसत तापमान के साथ वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून जून के मध्य से सितंबर के अंत तक चलता है। अक्टूबर और नवंबर के मध्य में मानसून के बाद या पीछे हटने वाले मानसून का मौसम होता है। उरई की सामान्य वार्षिक वर्षा 793.8 मिमी है। वार्षिक वर्षा का लगभग 90.4% मानसून के मौसम के दौरान प्राप्त होता है; वार्षिक वर्षा का केवल 9.6% अक्टूबर से मई के बीच होता है। अप्रैल में आर्द्रता सबसे कम होती है और पूरे वर्ष 26% और 83% के बीच बदलती रहती है। ग्राम पंचायत चुर्खी में मिट्टी का अत्याधिक महत्व है, क्योंकि मिट्टी के बिना कोई भी काम करना सम्भव नहीं है| मिट्टी के बिना आप किसी भी इमारत को नही तैयार कर सकते है । इसके अलावा जब बात आ जाएँ खेती की तो मिट्टी की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है, जिसमें किसानों द्वारा फसलो को तैयार किया जाता है| कहा जाये तो मिट्टी हमारे जीवन का एक अत्यंत महवपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना जीवन जीना असम्भव माना जाता है| ग्राम पंचायत चुर्खी में मुख्य रूप से पड़वा व हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती हैजो फसलों के लिए अत्यन्त उर्वर (उपजाऊ)) होती है। इसमें लगभग 40% सिल्ट,20% चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है। पानी तथा वायु के प्रवेश हेतु अर्थात् अधिक छिद्रिल होने के कारण फसलों की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। ऐसी मिट्टी अपने कुल भार का 50% पानी रोकने की क्षमता रखती है। इस मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा भी अधिक होती है। दोमट मिट्टी की जुताई चिकनी मिट्टी की अपेक्षा आसान होती है। इसमें सिल्टी मिट्टी की अपेक्षा हवा और पानी को छानने तथा जल-निकास की बेहतर क्षमता होती है। दोमट मिट्टी बागवानी तथा कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि किसी बलुई या चिकनी मिट्टी में भी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ मिले हों तो उसके गुण भी दोमट जैसे ही होंगे।

मुख्य फसले व उसके प्रकार

ग्राम पंचायत चुर्खी में मुख्य रूप से तीन प्रकार की फसले की जाती है (रबी, खरीफ और जायद) 80 प्रतिशत आबादी की आय का मुख्य श्रोत कृषि कार्य है और यंहा के लोग खेती से ही अपनी आजीविका चलते

[5] http://www.onefivenine.com/village.dont?method=displayVillage&villageId=193087
[6]District handbook- https://jalaun.nic.in/document/title-of-act-1-will-appear-here/

है | शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य बोया जाता है तथा फरवरी से अप्रैल के मध्य काट लिया जाता है। रबी की प्रमुख फसल - गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों अदि की फसले लेने के बाद खरीफ की फसल मानसून आने के साथ यानी मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है तथा मानसून लौटने के बाद सितम्बर से अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है। जिसमे तिली और बाजरा की फसले प्रमुख रूप से की जाती है कुछ किसान जायद फसलों की खेती रबी एवं खरीफ फसलों के मध्यवर्ती काल में की जाती है। इन फसलो को मार्च के बोया जाता है तथा जून में काट ली जाती है।जिसमे प्रमुख फसल- तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, टमाटर आदि शामिल है ।

2 अनुभाग 2

शोध की क्रियाविधि

दिव्यांग युवाओ को रोजगार व आजीविका से जुड़ने के लिए स्टडी को तैयार करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई: - इस सर्वे में प्राथमिक रूप से दो प्रकार के डाटा का इस्तेमाल किया गया प्रायमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा

- सेकेंडरी डाटा
  दिव्यांगजन के रोजगार व उनकी आजीविका के साधन और उनके दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं पर सेकेंडरी डाटा विभिन्न माध्यमों से लिया गया है
- इंटरनेट
- समाचार पत्र व उनके आर्टिकल
- विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट
- किताबें व मैगजीन एवं सरकारी अभिलेख
- जनगणना और विभिन्न अन्य सरकारी सर्वेक्षण
- आर टी आई जवाब
- बजट डेटा
- **प्रायमरी डाटा**
  1. व्यक्तिगत दिव्यांगजन के साथ सर्वे किया
  2. स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यक्तिगत बैठक

3. सरकारी अधिकारी के साथ व्यक्तिगत बैठक
4. वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठक
5. सामाजिक संस्थाओं व एनजीओ के साथ मीटिंग
6. संस्था निदेशकों के साथ मीटिंग
7. आशा, आंगनवाड़ी व ग्राम के बुजुर्ग लोगों के साथ बैठक
8. दिव्यांगजन के साथ व्यक्तिगत बैठक व परिचर्चा
9. दिव्यांगजन की राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक
10. स्वरोजगार संस्थाओं के साथ बैठक व सेंटर विजिट
11. दिव्यांगजन के ग्रुप के साथ बैठक व परिचर्चा
12. टेलिफोनिक ज़ूम काल इंटरव्यू के माध्यम से

प्राथमिक अध्ययन करने से पहले मैंने रोजगार से संबंधित समाचार पत्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए रोजगार करने के कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसका अध्ययन किया अध्ययन में युवा शक्ति संगठन के पंचायत लीडर के साथ मिलकर उनके पंचायतों में जाकर अध्ययन किया और वहां की रोजगार की स्थिति के बारे में जाना शुरुआत में मैंने **स्नोबॉल सेंपलिंग** के माध्यम से 18 से 45 आयु वर्ग के 10 व्यक्तियों के सर्वे करने के बाद प्रश्नावली तैयार की इसके बाद प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए विकास खंड अधिकारी से संपर्क किया, उसके बाद मैंने महेवा ब्लाक के जिन पंचायतों की आबादी ज्यादा थी उन पंचायतों का चयन किया | सर्वेक्षण में गूगल फॉर्म का उपयोग किया रोजगार व स्वरोजगार सम्बन्धित प्रश्न का उपयोग किया सर्वेक्षण करने कार्य योजना बनाया कार्ययोजना के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में डेटा एकत्र किया दिव्यांग व्यक्तियों के घर पहुचने आश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,ग्राम प्रधान , समुदाय के लोगो के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के घर जानकारी ली इस सर्वेक्षण में दिव्यांग व्यक्तियों के डोर टू डोर व्यक्तिगत कुल 95 घरो का सर्वेक्षण किया गया जो कि ग्रामीण स्तर रोजगार व स्वरोजगार जुड़ने की जानकारी व जुड़े उन समस्याओं का चिन्हाकित किया ! सर्वेक्षण के दौरान कुल 80 दिव्यांगजनों ने सर्वे शामिल हुए प्रारंभ में दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान स्नोबॉल नमूने के माध्यम से की गई और बाद में इसे राष्ट्रीय कृत नमूना करण के साथ मिला दिया गया अध्ययन में भाग लेने के लिए लोगों को जुटाने के लिए पंचायत के अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मदद ली गई |

नमूना

मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति, एक परिभाषित प्रक्रिया द्वारा सांख्यिकीय आबादी से एकत्र या चयनित डेटा नमूना:- नमूने के तत्व को नमूना बिंदु के रूप में जाना जाता है।

नमूना आकार:- 80

लक्षित दर्शक- पुरुष और महिला दोनों आयु समूह- 16-60 M/

साक्षरता

चुर्खी में पुरुषो की संख्या ज्यादा है साथ लडको को पढ़ाने पर जोर दिया जाता है वहीं महिलाओं को पढ़ाने में जोर नहीं दिया जाता है क्यों प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला और जूनियर हाईस्कूल है पर इंटर कालेज नही था तो इटर मीडिएट की शिक्षा को जरी रखने के लिए 6 किलोमीटर बाबई जाना होता था| जिससे लडकियों को आगे की शिक्षा पूरी करने में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि युमुना के नजदीक होने के कारण यंहा पर डकेतो का बहुत अधिक डर व् भय था जिससे लोग अपनी लडकियों को स्कूल भेजने में डरते थे | परन्तु वर्तमान में सरकार ने इंटर कालेज बना दिया गया जिससे यह समस्या लगभग ख़त्म हो चुकी है|[7]

गांव की कुल आबादी 4152 में से कुल 2135 लोग साक्षर हैं कुल साक्षरता दर 59.79%		
पुरुष	1394	70.51%
महिलाएं	741	46.49%

दिव्यांगजनों व उसकी वर्तमान स्थिति [8]

विश्व स्तर पर दिव्यांग लोगों की संख्या एक बिलियन है जो वैश्विक जनसंख्या का 15% है। 2011 जनगणना के अनुसार 2.21% लोग ही दिव्यांग है भारत में 2.68 करोड़ (26.8 [9]मिलियन) लोग दिव्यांग हैं। [10]2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन की संख्या 41 लाख 57 हजार 514 है। जो कि जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है।

[7] https://uphwd.gov.in/hi/article/publication

[8] http://www.ccdisabilities.nic.in/hi/resources/disability-india

[9] https://uphwd.gov.in

[10] https://etrace.in/census/village/churkhi-kalpi-district-jalaun-uttar-pradesh-151421

राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो 36% दिव्यांगजन के पास रोजगार है और वही 64% लोगों के पास रोजगार नहीं है | इसमें पुरुष कामगारों की संख्या 47% है और महिला कामगारों की संख्या 23% है | ग्रामीण भारत में, 25% महिला दिव्यांग काम कर रही हैं, जबकि शहरी भारत में, संगत आंकड़ा 16% है।[11]

जिला स्तरीय रोजगार की स्थिति

निम्नलिखित डाटा के अनुसार यह पता चलता है कि जालौन जिले में कामगारों की संख्या 32.9 % है, जिले में दिव्यांग कामगारों की संख्या की पुष्टि नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिव्यांग जनों के रोजगार व स्वरोजगार कि स्थिति के बारे में शोध किया जाए |

Workers and Non Workers							
Total Workers		Absolute			Work Participation Rate		
		Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
	Persons	65,814,715	51,950,980	13,863,735	32.9	33.4	31.2
	Males	49,846,762	38,352,879	11,493,883	47.7	47.4	48.9
	Females	15,967,953	13,598,101	2,369,852	16.7	18.3	11.3
Main Workers		Absolute			Percentage to total workers		
		Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
	Persons	44,635,492	33,538,817	11,096,675	67.8	64.6	80.0
	Males	37,420,299	27,812,347	9,607,952	75.1	72.5	83.6
	Females	7,215,193	5,726,470	1,488,723	45.2	42.1	62.8
Marginal Workers		Absolute			Percentage to total workers		
		Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
	Persons	21,179,223	18,412,163	2,767,060	32.2	35.4	20.0
	Males	12,426,463	10,540,532	1,885,931	24.9	27.5	16.4
	Females	8,752,760	7,871,631	881,129	54.8	57.9	37.2
Marginal Workers (3-6 months)		Absolute			Percentage to total marginal workers		
		Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
	Persons	16,885,149	14,491,868	2,393,281	79.7	78.7	86.5
	Males	10,156,804	8,531,773	1,625,031	81.7	80.9	86.2
	Females	6,728,345	5,960,095	768,250	76.9	75.7	87.2
Marginal Workers (Less than 3 months)		Absolute			Percentage to total marginal workers		
		Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
	Persons	4,294,074	3,920,295	373,779	20.3	21.3	13.5
	Males	2,269,659	2,008,759	260,900	18.3	19.1	13.8
	Females	2,024,415	1,911,536	112,879	23.1	24.3	12.8
Non Workers		Absolute			Percentage to total population		
		Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
	Persons	133997626	103366298	30631328	67.1	66.6	68.8
	Males	54633748	42640116	11993632	52.3	52.6	51.1
	Females	79363878	60726182	18637696	83.3	81.7	88.7

(District handbook 2011)

[11] Persons with Disabilities (Divyangjan) in India - A Statistical Profile : 2021- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nhfdc.nic.in/upload/nhfdc/Persons_Disabilities_31mar21.pdf

3 अनुभाग 3

शोध का विश्लेषण

अध्ययन का उद्देश्य

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार की स्थिति और नीतियां यह महेवा ब्लाक की तीन ग्राम पंचायत शामिल हैं | दिव्यांगजनों को रोजगार व स्वरोजगार और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को व्यक्तियों के बीच मांग करने पर बुनियादी रोजगार की स्थिति का पता लगाना |

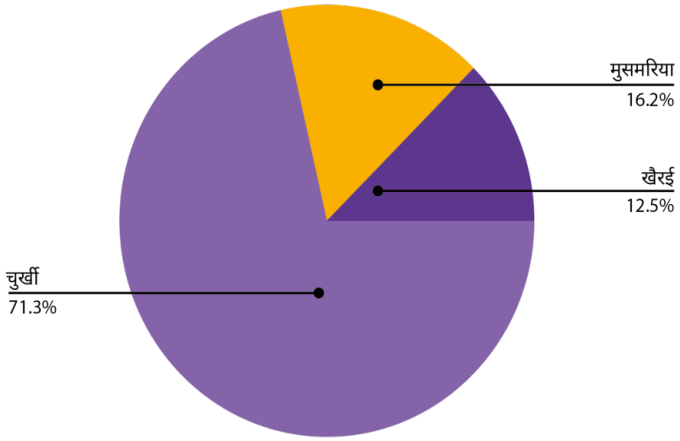

आयु वर्ग चुने

सर्वे में भाग लेने वाले का 7.50% है जो कि18 वर्ष से कम हैं | वही 19 से 35 वर्ष की आयु के कुल 41.25% है वही 36 वर्ष से 55 वर्ष की आयु के 35% है वही 56 से 64 वर्ष की आयु के 13.75% है और 65 से अधिक की आयु के सर्वेक्षण में 2.50 % दिव्यांगजनों ने सर्वेक्षण में भाग लिया है |

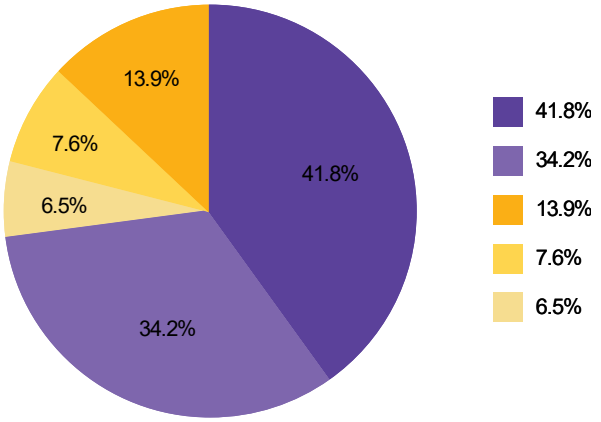

आयु वर्ग

लिंग

लिंग के आधार पर सर्वेक्षण में भाग लेने वाले दिव्यांगजन में 75% पुरुष और 25% महिलाओं है |

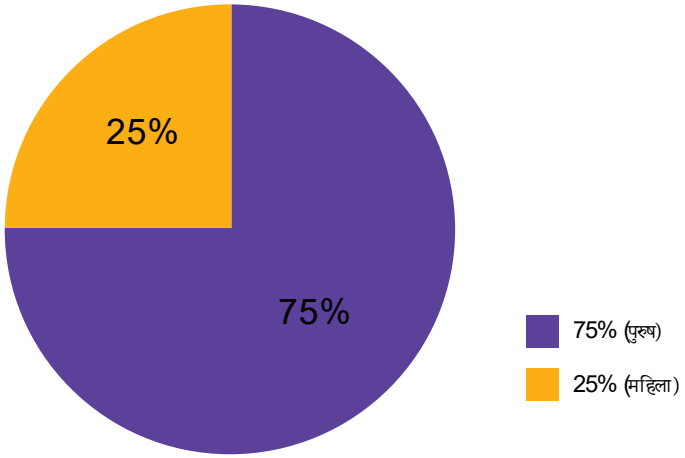

जाति वर्ग

जाति वर्ग	प्रतिशत %
अनुसूचित जाति (SC)	25
अनुसूचित जनजाति (ST)	0
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	37.5
अल्पसंख्यक - मुस्लिम (MINO)	11.25

सामान्य (GEN)	26.25

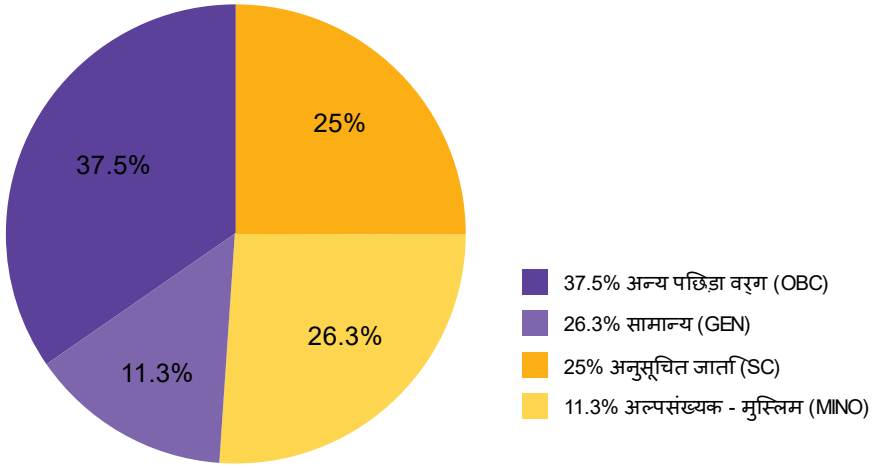

शिक्षा का स्तर

ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगजनों में सर्वे के अनुसार शिक्षा का परिदृश्य , कक्षा 1 से 5 तक 16.25% है, वही कक्षा 6 से 8 तक 27.50% है, वही दसवीं पास 8.75%है, वही इंटरमीडिएट 11.25% प्रतिशत है, स्नातक 5% है वहीं जो निरक्षर हैं वे 31.25% है | बेसलाइन सर्वे के अनुसार देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी दिव्यांगनजन की शिक्षा का स्तर कम है ।

इस रिपोर्ट[12] के अनुसार, भारत में 5 से 19 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों में चार में से कम-से-कम एक ने कभी किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग नहीं लिया, जबकि पाँच वर्षीय विकलांग बच्चों में से तीन-चौथाई स्कूल नहीं जा पाते।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-19 वर्ष के 78 लाख से अधिक विकलांग बच्चे हैं। इनमें से सिर्फ 61% बच्चे शैक्षिक संस्थान में भाग ले रहे थे। लगभग 12% बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, जबकि 27% बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए थे।
- स्कूल में नामांकित विकलांग बच्चों की संख्या स्कूलिंग के प्रत्येक क्रमिक स्तर के साथ गिरती है। लड़कों की तुलना में स्कूल में विकलांग लड़कियों की संख्या कम है।

[12] विकलांग बच्चों की स्कूलों में नामांकन स्थिति - Drishti IAS

- विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के बीच अंतर बना रहता है।
- 20% दृश्य और श्रवण दोष वाले बच्चे कभी स्कूल में नहीं थे।
- हालाँकि कई विकलांग या मानसिक बीमारी वाले बच्चों में यह आँकड़ा 50% से अधिक पाया गया।

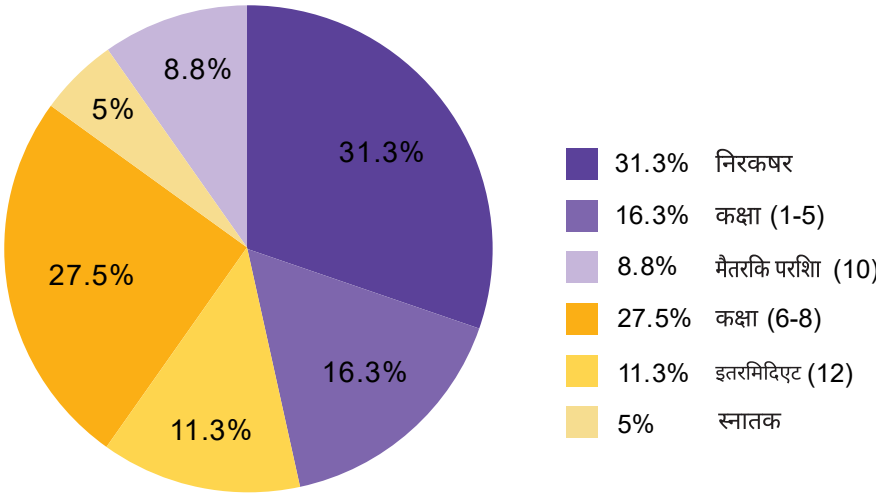

दिव्यांगजन की स्वरोजगार व रोजगार की स्थिति

- ग्रामीण स्तर पर सर्वे के अनुसार 15% लोगों के पास स्थाई रोजगार व स्वरोजगार हैं तथा 43.75% लोगों के पास अस्थाई तौर पर रोजगार है जिनको कभी-कभी कार्य मिलता है और वही 41.25% लोग किसी भी कार्य से नहीं जुड़े हुए |
- रोजगार की स्थिति देखते हुए यह जरूरी है कि योजनाएं जो राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वह जमीन तक पहुंचे और सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के समावेश हेतु प्रभावी ढंग से लागू हो| उनमें से मुख्य रूप से कुछ योजनाओ की जानकारी आवश्यक है |

अगर आप स्वरोजगआर से जुदे है तो कसि प्र्कर

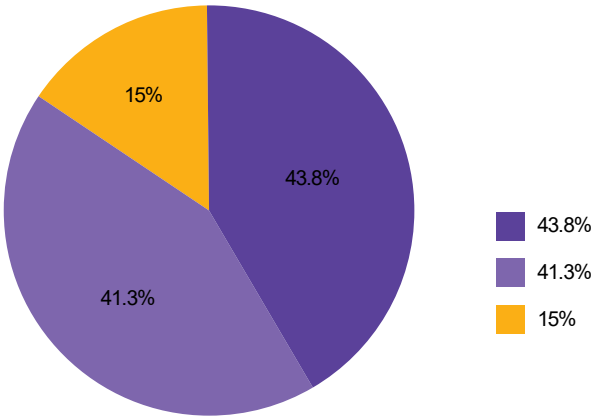

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

[13]राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार एन आर एल एम की शुरुआत स्थाई निर्धनों को सशक्त एवं स्थाई संस्थान बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार एवं हुनरमंद, मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाना जरूरतमंद सामाजिक समूहों में दिव्यांगजन भी एक हिस्सेदार हैं परंतु दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर कोई विशिष्ट कार्यक्रम या आवंटन आधिकारिक तौर पर नहीं है | ज्यादातर राज्यों में महिलाओं के समूह को विशेष रूप से सहायता प्राप्त होती है किन्तु दिव्यांग जनों के समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं किंतु उनके क्रियान्वयन हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है| [14]सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारिता मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग जनों के समूह को विस्तार देने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना लागू हुई 8 जुलाई 2023 को |

[13] https://rural.nic.in/sites/default/files/NRLM_Guidelines_English.pdf

[14] NRLM social inclusion handbook- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://nirdpr.org.in/nird_docs/nrlm/nrlmhandbookSocialInclusion050716.pdf

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। आजीविका गरीबी कम करने के लिए एक मिशन है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है | इस योजना का महत्व गरीबी कम करने की इसकी क्षमता से है। इसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इंडिया' के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई है। सामाजिक रूप से वंचित समूह के अनिवार्य कवरेज द्वारा उम्मीदवारों का पूर्ण सामाजिक समावेश सुनिश्चित किया जाता है। धन का 50% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, 15% अल्पसंख्यकों के लिए और 3% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए के लिए निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों में एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी चाहिए।

दिव्यांग पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण संचालन योजना

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण संचालन योजना के तहत दुकान निर्माण के लिए पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें 15,000 की धनराशि चार फीसद वार्षिक ब्याज पर ऋण के रूप में और पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं दुकान संचालन के लिए पात्र लाभार्थी को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 7,500 रुपये चार फीसद वार्षिक ब्याज पर व 2,500 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। योजना की पात्रता लाभार्थी कम से कम 40 फीसद या इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए। उसकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18-60 वर्ष के लाभार्थी इसके लिए पात्र होंगे। लाभार्थी के पास दुकान निर्माण के लिए 110 वर्ग फिट भूमि होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में दुकान निर्माण एवं संचालन योजना

[15]के तहत 910 दिव्यांग दिव्यांग जनों को 2020-21 में दुकान निर्माण के लिए 15 लाख रुपए तथा दुकान संचालन के लिए 91 लाख रुपए प्रदान किए गए और यह डाटा 2020-21 (31 मार्च 2021) तक का है |

पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण /दुकान संचालन योजना बजट का आकंडे[16]

अनुदान **राशी**

(धनराशि लाख रू. में)

वास्तविक अ 19-2019- 2020	आय- व्ययक अनुमा 2020 -2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020 -2021	आय व्ययक अनुमान 2021-2022	कुल बजट में दुकान संचालन योजना का प्रतिशत
26.38	26.51	18.03	26.51	0.028
वास्तविक आंकड़ 2020-21	आय व्ययक अनुमा 2021 -2022	पुनरीक्षित अनुमान 2021 -2022	आय व्ययक अनुमान 2022 -2023	कुल बजट में दुकान संचालन योजना का प्रतिशत
26.50	26.51	18.03	26.51	0.025

निवेश/ऋण राशि

(धनराशि लाख रू. में)

[15]पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण /दुकान संचालन योजना डेटा
https://drive.google.com/drive/folders/13vpV8JZ0FEGn2zkIlwdB_NOmdD441Cs2
[16] Open budgets india
https://www.openbudgetsindia.org/organization/about/uttar-pradesh

वास्तविक आंकड 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020 -2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020 -2021	आय व्ययक अनुमान 2021 -2022
79.53	79.53	79.53	79.53
वास्तविक आंकड 2020-21	**आय व्ययक अनुमान 2021 -2022**	**पुनरीक्षित अनुमान 2021 -2022**	**आय व्ययक अनुमान 2022 -2023**
79.50	79.53	79.53	79.53

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी. एम.के. वी.वाई.)"कौशल विकास योजना" कि शुरूवात 15 जुलाई 2015 से हुई, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, खासतर सूक्ष्म और न्यूनमध्यम वर्ग के लोगों के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें उनके कौशलों को सुधारकर उन्हें रोजगार के अवसरों और आर्थिक स्वावलंबन के लिए तैयार करना है। यह योजना समाज के विकलांग वर्गों, महिलाओं, युवाओं, और अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक स्वावलंबन के अवसर प्रदान करती है।

कौशल प्रशिक्षण: इस योजना के तहत, योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोगों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि कौशल शिक्षा, उद्योग कौशल, व्यापारिक कौशल, आदि।

ऋण सुविधाएँ: कुछ योजनाएँ वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं को प्रदान करती हैं, ताकि लोग व्यवसाय खोलने और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकें।

रोजगार के अवसर: योजना के अंतर्गत, सरकार रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करती है और उन्हें उनके कौशलों और प्रशिक्षण के आधार पर रोजगार प्रदान करती है।

उद्यमिता की संवर्धन: योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी है, ताकि लोग व्यवसाय आरंभ कर सकें और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें।

कौशल विकास योजना के तहत कई उपयोगी योजनाएँ हैं, जिनमें "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)" और "नौकरी योजना" शामिल हैं, जो भारतीय नागरिकों को उनके कौशलों को सुधारने और रोजगार के अवसरों को बेहतर तरीके से पहचाने में मदद करती हैं।

वही जब हम दिव्यांग व्यक्तियों की बात करते हैं तो वे निचले पायदान पर नजर आते हैं ऐसा ही शोध के दौरान दिखाई देता है |

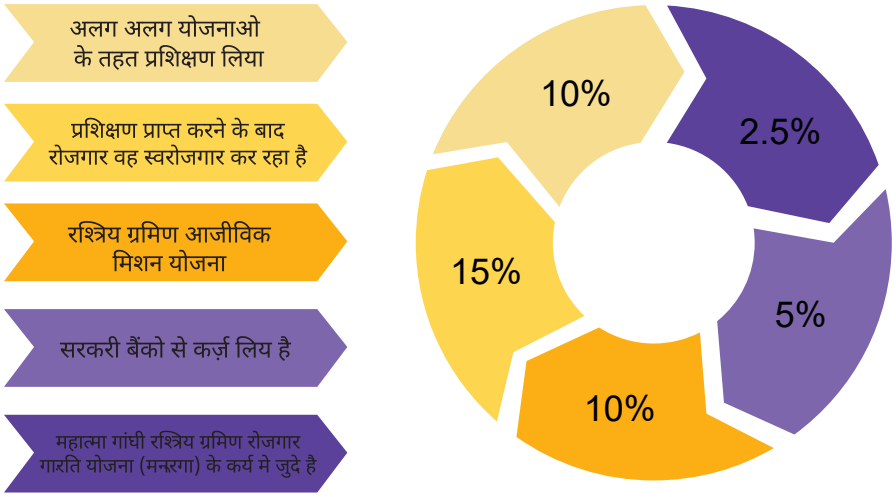

योजना से जुड़े हुए व्यक्तियों का प्रतिशत

आर टी आई में प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त डाटा से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण में [17]दिव्यांग जनों की प्रतिभागिता नगण्य है | प्राप्त जानकारी के अनुसार 2020 - 2021 में 0.48 % और 2021-2022 में 0.03 % से यह स्पष्ट नजर भी आता है |

वर्ष	कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या	प्रशिक्षित उम्मीदवारों में दिव्यांग का प्रतिशत
2020-2021	1731432	8453	0.48 %
2021-2022	442710	164	0.03 %

(श्रोत-राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा प्राप्त आरटीआई का उत्तर)

कौशल विकास केंद्र की स्थापना[18]

(धनराशि लाख रू. में)

[17]RTI(NSDC)Response https://drive.google.com/file/d/1LfmJP4YAYzyn5VV3TDn_8KYVSYmMPcY3/view?usp=drive_link

[18]https://drive.google.com/file/d/1LfmJP4YAYzyn5VV3TDn_8KYVSYmMPcY3/view?usp=drive_link BUDGET ESTIMATE 2021-22 https://openbudgetsindia.org/dataset/up-expenditure-social-welfare-department-handicapped-and-backward-class-welfare-2021-22

वास्तविक आंकड़ 2020-21	आय- व्ययक अनुमान 2021 -2022	पुनरीक्षित अनुमान 2021 -2022	आय व्ययक अनुमान 2022-2023	कुल बजट में कौशल विकास केंद्र की स्थापना का प्रतिशत
वास्तविक आंकड़ 2019-2020	आय- व्ययक अनुमान 2020 -2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020 -2021	आय व्ययक अनुमान 2021-2022	कुल बजट में कौशल विकास केंद्र की स्थापना का प्रतिशत
26.52	23.01	22.88	30.96	0.028
25.33	30.96	30.83	31.01	0.024

"द वायर"[19] के आर्टिकल के अनुसार वर्तमान केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय योजनाओं के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण और रोजगार में उल्लेखनीय गिरावट आई है। एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि पी एम के वी वाई और एन एच एफ डी सी जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत प्रशिक्षित और नियोजित लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, पी एम के वी वाई के तहत, प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या लगभग 99% कम हो गई, 2019-20 में 22,852 से 2021-22 में 246 हो गई। इसी तरह, इन योजनाओं के तहत रोजगार के आंकड़ों में भी भारी गिरावट देखी गई। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर प्रदान करने में इस गिरावट के पीछे के कारणों को प्रदान की गई जानकारी में स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

[19] https://thewire.in/government/training-employment-of-persons-with-disabilities-drops-under-central-schemes-in-2nd-modi-regime

केस स्टडी

हरिवंश कुमार 28 ग्राम सोहरापुर के रहने वाले हैं | जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जालौन जिले की कालपी तहसील से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सोहरापुर में शिक्षा का उचित संसाधन ना होने के कारण हरिवंश कुमार ने 12 वी तक शिक्षा ग्रहण की है हरिवंश के पिता पेशे से एक राजमिस्त्री कारीगर हैं उन्होंने हरवंश का पालन पोषण मेहनत मजदूरी कर किया हरिवंश के परिवार में तीन भाई और दो बहने हैं हरिवंश अपने पिता के सबसे छोटे और तीसरे पुत्रो में तीसरे पुत्र हैं हरिवंश जन्म से ही 95 % लोकोमोटर डिसेबिलिटी का शिकार है जिससे उनके प्रारंभिक जीवन में उनको व उनके परिवार को परेशानियां उठानी पड़ी साथ ही हरिवंश अनुसूचित जाति से आते हैं जिसके कारण उनके परिवार को और उनको एक अछूत सा देखा व व्यवहार किया जाता है हरिवंश की सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी है और सभी लोग हरवंश से अलग होकर अपना अपना जीवन सुख से व्यतीत कर रहे हैं पर हरवंश के मातापिता आज भी हरिवंश के साथ ही रहते हैं|

इन्होंने कौशल विकास योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रखा है संसाधन की कमी के अभाव इलेक्ट्रिशियन के काम को अपने अपनी आजीविका का साधन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि दुकान रखने के लिए लोग मोटा किराया और तगड़ी रकम गारंटी के तौर पर मांगते हैं मांगते हैं | स्वरोजगार करने के लिए उन्होंने एक बार लोन के लिए आवेदन किया था लेकिन उनका उसका कोई जवाब नहीं मिला जिससे हताश होकर उन्होंने कभी भी दोबारा से कोशिश नहीं की। कालपी मंडी समिति में दो बार लोन के संबंध में बात हुई उन्होंने आश्वासन दिया कि हां हम तुम्हारा लोन कर देंगे पर किया नहीं। बैंक में गारंटर ना होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो हमारे कुछ साथी जो हमें बहुत प्रोत्साहन करते हैं और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।

वर्तमान समय में हरिवंश अपने भरण-पोषण के लिए एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं जिससे उनकी अजीब का गुजर बसर होती है इसमें उनके माता-पिता भी मदद करते हैं और 200 रूपये तक कमा लेते हैं।

दिव्यांग प्रमाण पत्र कि स्थिति

सर्वे के अनुसार भाग लेने वाले दिव्यांगजन के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है जो की 71.25 % है वही 28.75% दिव्यांग ऐसे हैं जिनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है | दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है अगर इनके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है तो वह सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के लाभ नहीं उठा सकते हैं |क्योंकि 1 अप्रैल सन 2023 से योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए यूडी आईडी कार्ड का होना अनिवार्य है हालाकि हम SIPDA को देखें तो इसमें बजट की स्थिति कम इस्तेमाल को दर्शाती है |

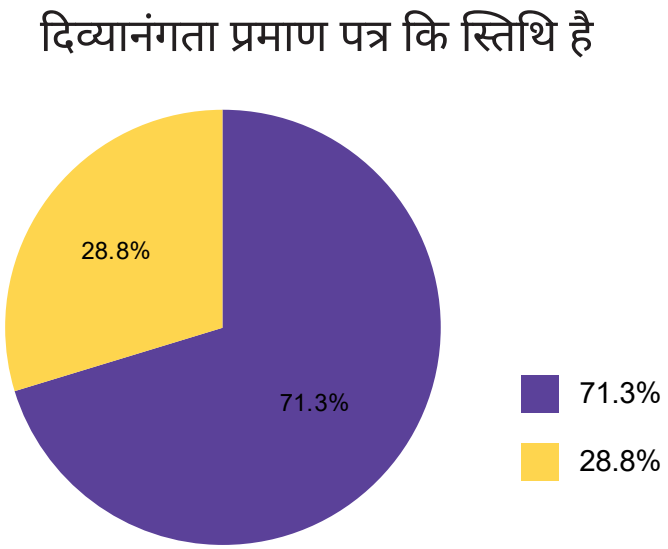

शोध के दौरान जब मैंने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया सरकार अपनी ओर से लोगों को जागरूक करती है परंतु उनके पास योजनाओं में उतना बजट नहीं हो पाता है कि वह व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर जन-जन तक योजनाओं को पहुंचा सकें जिससे लोग जानकारी से अछूते रह जाते हैं और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है उसी की तुलना में कुछ लोग जो सामान्यतया विभागों और जागरूक लोगों के संपर्क में रहते हैं वह योजनाओं का लाभ उठा ले जाते हैं |

क्या आपको स्वरोजगार के तरह सरकरी योजनाओ की जनकरी है

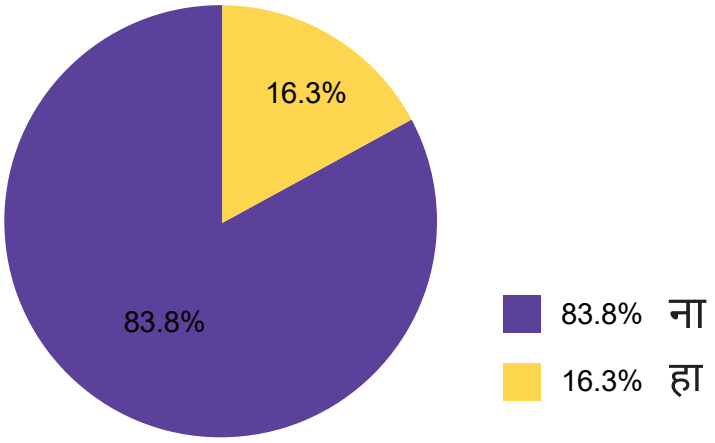

UDID (विशिष्ट विकलांगता पहचान) परियोजना सिपडा (कार्यान्वयन योजना) के अंतर्गत आती है

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम) जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना है। 1 जून, 2021 की अधिसूचना के अनुसार, यह अनिवार्य हो गया कि विकलांगता प्रमाण पत्र केवल यूडीआईडी स्वाबलंबन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। जैसा कि 06 जून, 2023 को समाचार में बताया गया था, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा था कि 716 जिलों में 94.30 लाख UDID उत्पन्न की गई है। 05 जुलाई 2023 को प्राप्त एक आर टी आई उत्तर के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 303383 और जालौन जिले में यह संख्या 16729 है | हम SIPDA योजना के बजट आवंटन में देख सकते हैं कि संशोधित बजट अनुमान बहुत कम है, 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती जिसमें UID परियोजना भी शामिल है, केंद्र सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है। यह विकलांग व्यक्तियों के विभाग के कुल परिव्यय का केवल 13 प्रतिशत है।

क्या आप के पास यु डी ओई कार्ड है (UNIQUE DISABILITY ID)

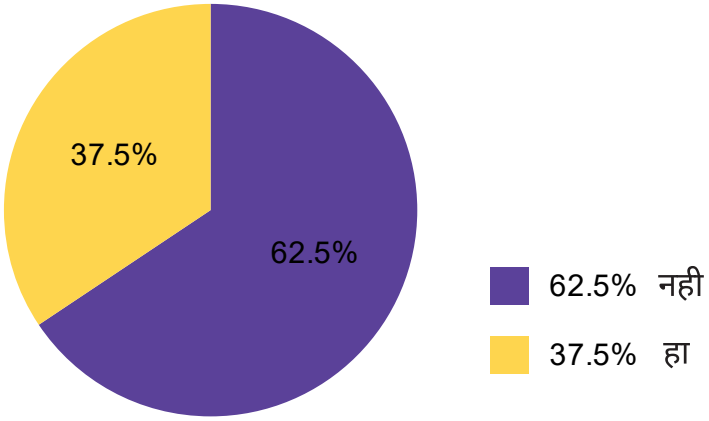

UDID परियोजना के लिए कुल बजट आवंटन 98.753 करोड़
व्यय का वर्षवार आँकड़ा

2016-17	2.11
2017-18	2.41
2018-19	7.01
2019-20	7.87
2020-21	5.10
2021-22	5.83
2022-23	6.50
2023-24	3.10 (as on 01.08.2023)
TOTAL	39.93

जैसा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है, व्यय वर्षों में कुल आवंटन का केवल 40 प्रतिशत है।

डेटा 27.07.2023 तक का

UDID	Total	MALE	FEMALE	OTHERS
application	10270677	6857297	3411060	2319
active	8842020	5913172	2926995	1852

सिपडा (SIPDA)

एस आई पी डी ए में यू डी आई डी परियोजना के लिए बजटीय आवंटन शामिल है और हम देख सकते हैं कि आवंटन में गिरावट की प्रवृत्ति है जो यूडीआईडी परियोजना सहित विकलांग व्यक्तियों की पहुंच, अनुसंधान, कौशल निर्माण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करती है। हम इसे एक पैटर्न के रूप में देख रहे हैं जहां संशोधित बजट अनुमानित बजट से आधे से भी अधिक है |

SIPDA's outlay of expenditure	20-'21	21-'22	22-'23	IN CRORE 23-'24
Budget Estimate	251.5	209.77	240.39	150
Revised Estimate	122.89	147.31	100	NA
SIPDA's outlay out of department's outlay (in%)	**20-'21**	**21-'22**	**22-'23**	**23-'24**
Budget Estimate	18.97554682	17.90197735	19.82728757	12.24339877
Revised Estimate	13.65444444	14.1059647	9.842713439	NA

दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है उसका क्या कारण है |

40% दिव्यांग व्यक्ति को कहना है कि जानकारी नहीं है ,24% का कहना है कि जिला चिकित्सालय की दूरी ज्यादा है, 8% का कहना है कि परिवार का सहयोग नहीं मिलता , 8% का कहना है कि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है ,20% का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का सहयोग न होने के कारण वहीं केस स्टडी में नजर भी आता है |

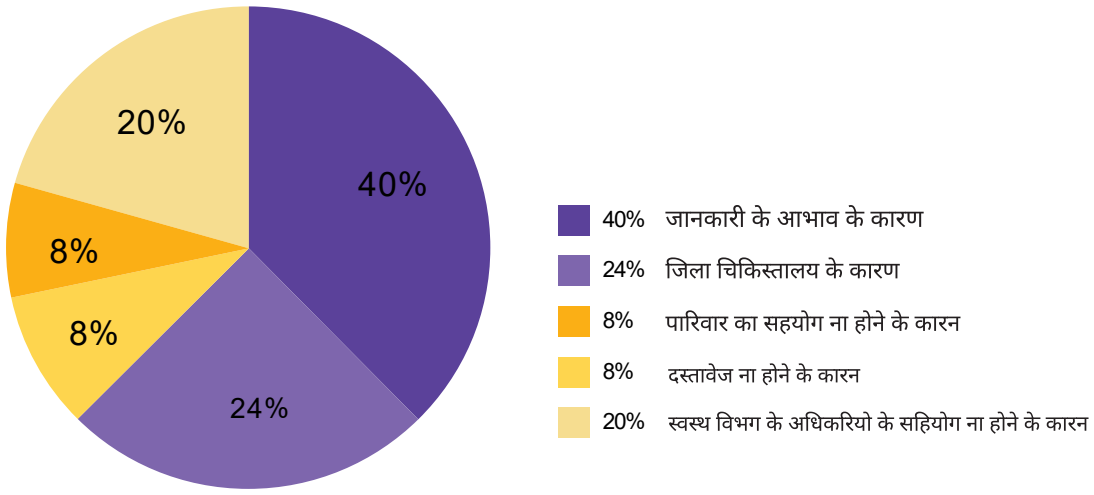

केस स्टडी

आजाद शाह बुंदेलखंड के यमुना किनारे बसे हुए जिला जालौन के महेवा ब्लाक में ग्राम पंचायत चुर्खी के रहने वाले हैंआजाद के परिवार में उनकी पत्नी एक बेटा और दो बेटियां हैं आजाद दाए पैर से विकलांग है पूरा परिवार आजाद के ऊपर निर्भर है जैसा की आदत बताते हैं कि यह विकलांगता उनके जन्म के साथ नहीं जुड़ी हुई थी |

उन्होंने बताया कि वह सामान्य लोगों की तरह थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था । आजाद जी राजमिस्त्री का कार्य करते थे 22 नवंबर 2019 को सड़क दुर्घटना में वह अपने एक पैर से अपाहिज हो गए।

आजाद शाह ने बताया कि आज तक उनको सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है उन्होंने बताया कि मैंने दो बार दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और मैं वहां पर जांच कराने गया तो उन्होंने मुझे यह कहकर वहां से भगा दिया कि आपका तो पैर सही है और वही अगर मैं अगर उनको रिश्वत डे दो तो मेरा काम हो जाएगा पर मेरे पास रिश्वत देने लायक पैसे नहीं है ।

आजाद कहना है कि मैं शिक्षित नहीं हूँ जिससे मुझे सरकार कि कोई भी योजनाओ कि जानकारी नहीं मिल पाती है जब यदि सरकार गांवों में मेरे जैसे बिना पढे लिखे सैकड़ों लोग है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के लाभ से वंचित है |

“सरकार टीवी में तो दिखात है कि जा योजना से तुमाई जिंदगी सुधार जेहे, बा योजना से काम मिल जे और तुमाये बच्चा पढ़ जेहे पर सही में कछु नहीं होत है हम लोग वही-वही रह जात है पैसा है ताकत है तो सब हो जात”

जब भी कार्ड विकलांग सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं |वह झांसी तो कहीं कानपुर के लिए लिख देते हैं की जांच कर कर आओ और मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि मैं जांचकर लूं मैं पिछले 3 वर्षों से अपना कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं बनवा पाया हूँ जब तक कार्ड नहीं बनेगा तब तक योजनाओ का लाभ कैसे मिलेगा ।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार

क्या आप दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से अवगत हैं।	प्रतिशत %
हां	5
नहीं	95

सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक भी दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगता अधिनियम के बारे मे जानकारी नहीं है | वहीं इस अधिनियम को एक विस्तृत अधिनियम माना जाता है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। इस अधिनियम की जानकारी जमीनी स्तर पर दी जाए तभी दिव्यांग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे |

उत्तर प्रदेश के कुल बजट का सारांश

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की जनसंख्या 41 लाख 57 हजार 514 है। जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है।[20] बजट जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बजट में समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) आवंटित बजट 2019-2020 में 0.22% , 2020 - 2021 में 0.21% , 2021 2022 में 0.20% और 2022-2023 में 0.24% है जो की आवादी के हिसाब से कम है यह स्पष्ट नजर की भी आता है |

(धनराशि करोड़ रू. में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश के कुल बजट आय व्ययक का अनुमान	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) आवंटित बजट आय व्ययक का अनुमान	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) आवंटित बजट का प्रतिशत
2022-2023	582956	1428.72	0.24%
2021-2022	550271	1150.54	0.20%
2020-2021	512861	1095.35	0.21%
2019-2020	479701	1060.28	0.22%

[20] PRS india
https://hi.prsindia.org/budgets/states

(धनराशि लाख रू. में)

Financial Year	आय व्यय का अनुमान Estimated Expenditure	पुनरीक्षित अनुमान Revised Expenditure	वास्तविक व्यय Actual Expenditure
Financial Year 2022-23	142872.53	NA	NA
Financial Year 2021-22	115054.66	131754.66	NA
Financial Year 2020-21	109535.63	109535.63	103702.7
Financial Year 2019-20	106028.14	21106910.48	92379.74

[21] Performance budget UP Handicapped empowerment department https://uphwd.gov.in/hi/article/budget

4 अनुभाग 4

निष्कर्ष

दिव्यांग युवाओं को रोजगार स्टडी के जालौन जिले के महेवा ब्लाक में एनसीपीईडीपी ओर से दिव्यांग युवाओं को रोजगार स्टडी की गई जिसमें प्राथमिक रूप है कुछ डांटा एकत्रित किया और उसके उपरांत गांव के लोगों से मुलाकात की और अपनी पहचान बनाई साथ ही ग्राम प्रधान व ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों व जिला स्तर पर अधिकारियों और संस्था व संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की और दिव्यांग जनों की उसमें भी सहभागिता की और पाया दिव्यांगजन की स्थिति जस के तस है है और स्टडी के दौरान मैंने पाया कि ग्रामीण स्तर पर दिव्यांगजन के साथ कार्य करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि दिव्यांग लोगों को कानूनों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बिल्कुल नहीं है साथ ही उनको सरकारी योजनाओं से अनभिज्ञ है, दिव्यांगजन के हित के लिए सामाजिक स्तर पर भी कार्य करना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आज ही रूढ़िवादी सोच और सामाजिक उत्पीड़न दिव्यांगजन के साथ जारी है जिस पर विभिन्न ट्रेनिंग, नुक्कड़ नाटक व जागरूकता कैंप के माध्यम से उनको जागरूक करना पड़ेगा जिससे समाज के बहिष्कार से दिव्यांगजन को मुक्ति मिल सके |

बेस लाइन सर्वे के उपरांत अवलोकन तथा सुझाव

शोध के उपरान्त ये कहाँ जा सकता है कि हमें दिव्यांगता के बारे में सामाजिक स्तर लोगों की सोच बदलने की जरूरत है | हमें दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने के लिए प्रयासरत और योजना योजनाबद्ध तरीके से सशक्त करना होगा जिसमें शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है | शोध में एक उदहारण पाया गया कि एक दिव्यांग व्यक्ति को सुबह सुबह उठकर वह किसी ऐसे व्यक्ति के घर के दरवाजे से निकल गया तो लोग उसे देख कर कहने लगे, "यह कहने सुबह सुबह हमने कहां से लंगड़े का मुंह देख लिया आज हमारा दिन अशुभ हो गया" इस कथन से यह स्थापित होता है कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हीन भावना है |

ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र सशक्तिकरण के लिए सिफारिशें

- चूंकि दिव्यांग व्यक्तियों की आबादी बदलती रहती है और विभिन्न समुदायों और भूगोल में फैली हुई है, इसलिए जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक वार्षिक सर्वेक्षण होना चाहिए जिसमें लिंग और दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के बीच अलग-अलग डेटा शामिल हो जो ग्राम में विभिन्न शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं को दर्शाता हो। पंचायत स्तर निश्चित अंतराल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण।

- आरपीडब्ल्यूडी 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों का आकलन करने के लिए हर छह महीने में, जैसे दिव्यांग प्रमाणीकरण, पेंशन, दिव्यांग बच्चों का नामांकन और आंगनवाड़ी केंद्रों में उनकी प्रगति।
- पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन के सहयोग से समुदाय के मुद्दों को उजागर करने और हल करने के लिए ब्लॉक और जिले में DPO का गठन, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की सभी युवाओ की आबादी शामिल हो ।
- दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमशीलता क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पंचायत में दिव्यांग व्यक्तियों के SHG का गठन।
- दिव्यांग व्यक्तियों को उद्यम के विभिन्न अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए RSETY, जिला रोजगार कार्यालय, KVK (कृषि विज्ञान केंद्र) और नाबार्ड के साथ सहयोग। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं और बाजार की स्थानीय जरूरतों का आकलन करने के लिए व्यापक अध्ययन होना चाहिए। प्रशिक्षण केंद्रों की पहुंच, संसाधन व्यक्तियों का संवेदीकरण और पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री की पहुंच।

- **अध्ययन की सीमाएँ**

- हस्तक्षेप का चयनित क्षेत्र महेवा ब्लॉक में तीन ग्राम पंचायतों तक सीमित है, इसलिए अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग ब्लॉक या जिले जैसे किसी भी बड़े क्षेत्र में सामान्यीकृत प्रवृत्ति को पेश करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- यह एक अवलोकन अध्ययन है, इसलिए जब दिव्यांग व्यक्तियों के साथ बातचीत करने और उनकी दिव्यांगजन का निर्धारण करने की बात आती है तो यह चिकित्सकीय कानूनी जांच का दावा नहीं करता है।
- यह एक घरेलू सर्वेक्षण नहीं है, इसलिए यह तीन ग्राम पंचायत के प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को शामिल करने का दावा नहीं करता है |

5 अनुभाग 5

Annexure: :(रिफरेंस)

- श्री शारदा प्रसाद वर्मा सेवा संस्थान उरई के संस्थापक सिद्ध शिवहरे जी के साथ मीटिंग की
- सहायक विकास अधिकारी पंचायत के साथ मीटिंग की
- समुदाय के साथ बैठक की
- जन सुविधा एकल खिड़की संचालक के साथ मीटिंग
- जन साहस के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उमेंद्र सिंह के साथ मीटिंग की
- खंड विकास अधिकारी के साथ मीटिंग
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक सुपरवाइजर के साथ मीटिंग
- अरुण कुमार सिंह झारखंड राष्ट्रीय विकलांग मंच के महासचिव जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग
- RSETI के निर्देशक विभास कुमार शाह जी के साथ मीटिंग
- राष्ट्रीय अखिल भारतीय दिव्यांग परिषद के संस्थापक श्री अजय सिंह के साथ मीटिंग
- श्रीमान लुई नेत्रहीन आवासीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री तेजपाल राजपूत जी के साथ मीटिंग की
- कौशल विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सकुशल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के निर्देशक बृजेश दीक्षित जी के साथ मीटिंग की
- जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी के साथ मीटिंग
- समुदाय में बैठक की मेंटर के साथ जालौन
- ग्राम प्रधानो के साथ बैठक मंगरौल चुर्खी मुसमरिया
- ग्राम विकास अधिकारी मुसमरिया के साथ बैठक
- ग्राम- पंचायत मुसमरिया की आगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मीटिंग की
- राजकीय औधयोगिक प्रशिक्षण संस्थान उरई के फॉरमेन के के चतुर्वेदी जी के साथ बैठक
- **कुछ महत्तपूर्ण लिंक्स**
- https://uphwd.gov.in
- http://www.onefivenine.com/india/villages/Jalaun/Maheva/Churkhi
- http://www.onefivenine.com/india/villages/Jalaun/Maheva/Churkh
- https://etrace.in/census/village/churkhi-kalpi-district-jalaun-uttar-pradesh-151421

- https://www.findlatitudeandlongitude.com/l/Churkhi+Road%2C+Aunta%2C+Uttar+Prdrishtiiasadesh+285001%2C+India/5358025/
- https://www..com/hindi/tags/Issues-Related-to-Disability
- http://www.nhfdc.nic.in/upload/nhfdc/Persons_Disabilities_31mar21.pdf
- https://www.openbudgetsindia.org/
- https://www.amarujala.com/education/the-hans-foundation-brings-handbook-for-disabled-people-rights
- https://www.drishtiias.com/hindi/tags/Issues-Related-to-Disability
- https://enabled.in/wp/handbook-rights-persons-disabilities-act-2016/
- **मीडिया कवरेज**
- https://jalauntimessite.wordpress.com/2022/06/18/information-about-government-schemes-given-to-handicapped-people/
- https://thewire.in/government/training-employment-of-persons-with-disabilities-drops-under-central-schemes-in-2nd-modi-regime
- https://jalauntimessite.wordpress.com/2022/04/27/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0/
- https://jsnews.in/expand.php?id=news974540

अधिकारों को दिए गए पत्र

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQ_GfarEnIIKT4bdreTnhOcC3OHoTLi0

हस्ताक्षर सूची

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jH5ndb48ADhKyApkrHwvbdeoId4Wyik8

फोटोज

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ALiziBkjXvSx35E3JzAF_CfBE6t8mtmv

सहमति पत्र

https://drive.google.com/drive/home

सर्वे फार्म लिंक

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVdDXFND3GF

aIQXvcqjPgOiX1TwodXAcG-LSM0Umbm3hpT6Q/viewf